राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 60 (10) ग्रावि/नरेगा/लोकपाल/14–15 जयपुर, दिनांक

23 FEB 2015

विज्ञप्ति

लोकपाल अपीलेट आथोरिटी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण

केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 27 (1) के तहत राज्यों में लोकपाल नियुक्त करने हेतु अपने आदेश क्रमांक जे. 11011/21/2008/नरेगा/दिनांक 16.01.2014 द्वारा संशोधित निर्देश जारी किये है। उक्त निर्देशों की पालना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत योजना क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त होने वाली विभिन्न शिकायतों एवं अभाव अभियोग के निराकरण की प्रभावी प्रणाली जिलों में स्थापित करने हेतु जिलों में लोकपाल नियुक्त किये हुये है। दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 13.4 में लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरूद्व अपील की सुनवाई हेतु तीन सदस्यीय अपीलेट आथोरिटी का गठन किये जाने का प्रावधान है। राज्य स्तरीय अपीलेट आथोरिटी में निम्नांकित तीन सदस्यों की नियुक्ति हेतु पात्र एवं योग्य अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 31-03-2015 तक रजिरटर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/ई–मेल से आमंत्रित किये जाते हैं :–

(1) सेवानिवृत्त सिविल सर्वेन्ट – एक (2) शैक्षिक व्यक्ति – एक
(3) प्रतिनिधि, सिविल सोसायटी – एक

ईमेल पता:– nrega.raj@gmail.Com
विभागीय पता:– आयुक्त नरेगा एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
कमरा नः 8121, उत्तरी पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय जयपुर।

अपीलेट आथोरिटी हेतु शर्तें निम्न प्रकार से है :–

1. आवेदनकर्ता प्रतिष्ठित, निष्ठावान, विवाद रहित, अखण्ड सत्यनिष्ठा एवं गैर राजनैतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो तथा जिसे लोकप्रशासन/शैक्षणिक/सामाजिक कार्य का कम से कम 30 वर्ष का अनुभव हो। आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 66 वर्ष से अधिक नहीं हो।
2. आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ हो ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों मे निरीक्षण व भ्रमण कर सकें।
3. नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष के लिये होगी, जो कार्य मूल्यांकन के आधार पर 1–1 वर्ष के लियें दो बार बढायी जा सकेगी परन्तु 68 वर्ष की अधिआयु पर नहीं बढायी जायेगी।
4. पैनल राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुशंषित किया जावेगा तथा नियुक्त व्यक्ति को नियमानुसार मानदेय देय होगा।
5. मनरेगा में लोकपाल के रूप में एक वर्ष पूर्ण करने वाले आवेदको को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
6. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी के लिये विभागीय वेबसाइट www.nrega.raj.nic.in देखे।

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना परिषद,जयपुर
लोकपाल अपीलेट आथोरिटी के पैनल हेतु आवेदन पत्र

भाग अ – व्यक्तिगत सूचना

1. नाम बडे अक्षरों में (हिन्दी में).....
(अग्रेजी में).....
2. पिता/पति का नाम .....
3. जन्म तिथि.....(प्रमाण पत्र संलग्न करें).
4. आयु.....(दिनांक 01.01.2015 को)
5. डाक का पता (अ) वर्तमान पता.....
.....
(ब) स्थाई पता.....
.....
(स) दूरभाष नम्बर एसटीडी कोड सहित.....
(द) मोबाइल नम्बर.....
(य) ईमेल आईडी.....
6. क्या आप मानसिक व शारीरिक रुप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु स्वस्थ है (इसके लिये किसी भी राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. क्या आप किसी राजनैतिक पार्टी के सदस्य है (सदस्य नहीं होने का नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ –पत्र संलग्न करें)
8. क्या आप का कभी किसी अपराधिक केस मे चालान हुआ (यदि हॉ तो विवरण दे, यदि नही तो इस आशय का नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ–पत्र संलग्न करें।
9. क्या आप महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में किसी भी रुप में जुडे रहे है, यदि हॉ तो विवरण दे–कब, कहॉ, किस रुप में है ?----------
---

---
10. प्रार्थना पत्र के साथ दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अनुशंसा पत्र संलग्न करे, एवं इन संदर्भित व्यक्तियों के नाम, पते एवं दूरभाष नम्बर भी अंकित करें।

भाग ब – शैक्षणिक योग्यताः–

शैक्षणिक योग्यता.....(स्वसत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

अनुभव वर्षों में.....। अनुभव का क्षेत्र :– प्रशासन/ शैक्षणिक/समाज सेवा/(स्वसत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. सेवारत रहते हुये प्रथम नियुक्ति पद.....एवं दिनांक.....

   सेवानिवृत्त पद.....एवं दिनांक .....

4. किसी सामाजिक/व्यावसायिक संस्था के सदस्य रहे है तो संस्था का विवरण देवें.....

   .....

5. वर्तमान व्यवसाय.....

भाग स–घोषणाः–

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनायें सत्य है। मैंने विज्ञापन में वर्णित भारत सरकार द्वारा जारी लोकपाल संबंधी दिशा–निर्देशों को पढ लिया है और मुझे पता है कि लोकपाल अपीलेट आथोरिटी का कार्य एक अंशकालीन कार्य है। अपीलेट आथोरिटी को महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, नियम व योजना के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करना है।

स्थान आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक आवेदक का नाम

Instructions for Appellate Authority

13.4 State Government shall set up a three member Appellate Authority, consisting of an academician, a retired civil servant and a civil society representative, to consider representation by any party aggrieved by the awards of the Ombudsman. Such a representation shall be disposed of within a period of two months by the appellate authority. Office of the appellate authority shall be located in the office of the nodal department of the State Government implementing MGNREGA. Expenses of such an appellate authority shall be borne by States from the 6% administrative expenditure permitted under section 22(1)(c) of the MGNREGA.

13.4.1 Following are essential qualifications to be a Member of Appellate Authority:

i. **Minimum 30 years of experience in academics (teaching) or civil service or civil society organisation;**

ii. **Person with eminent standing and impeccable integrity;**

iii. **Not a member of any recognised political party or currently banned organisation;**

iv. **Physically active, capable of and willing to conduct filed visits to remote rural areas in the State;**

v. **Below 66 years of age at the time of appointment**

13.4.2 Those who have completed at least 1 year as MGNREGA Ombudsman will be given preference.

13.4.3 Members of Appellate Authority will have a tenure of 02 (two) years extendable not more than twice by one year each based on a performance appraisal process or till the incumbent attains the age of 68 (sixty eight) years, whichever is earlier. There will be no reappointment.

13.4.4 Senior most of three Members of the Appellate Authority will be the Chairperson. The Chairperson will allocate works (appeals) among Members, including him/herself for consideration and report to the Authority.

13.4.5 Work of Chairperson and Members of Appellate Authority is in the nature of *pro-bono* public service and no post is to be created.

13.4.6 Chairperson and Members of Appellate Authority will be entitled to get Rs.1500/- as sitting fee with an upper limit of Rs. 30,000/- in a month. Sitting means per day functioning, irrespective of number of cases handled and its duration in terms of working hours. State Government may pay an additional amount, over and above the sitting fee prescribed by the Ministry, from its own financial resources. A sitting could be for a full day or part.

13.4.7 For office work, the Appellate Authority shall operate from the premises of the State nodal Department implementing MGNREGA and necessary logistics and administrative support will be provided by the office of Secretary/Commissioner MGNREGA. TA/DA at rates admissible to Class-I officers of the State Government may be allowed. State Government may provide vehicle(s) from its local pool to the Appellate Authority for official purpose as per need. However, no new vehicle can be purchased for the use of Appellate Authority from MGNREGA fund. In case of travel by Chairperson or Members of Appellate Authority in his/her own or hired vehicle for official purpose, State Government concerned may reimburse the cost of travel, including waiting charges. State Government may fix rates for the purpose.

13.4.8 Parties aggrieved by the awards of Ombudsman must make a signed written appeal to the Appellate Authority within 15 days of the submission of such finding with a copy of awards and recommendations by Ombudsman. The Appellate Authority shall dispose an appeal within 2 months from the date of receipt. All decisions of the Appellate Authority on appeals against the awards of Ombudsman will be taken by all three Members together. In case of lack of consensus, all decisions will be made by majority of the three, including the Chairperson. Decision of the Appellate Authority shall be final and binding on the original parties of the case and on the Ombudsman concerned. It will be the responsibility of Principal Secretary/ Secretary, Nodal Department to enforce the decision of the Appellate Authority.

13.5 A representative of Programme Officer/ District Programme Coordinator may appear in cases where the Programme Officer/ District Programme Coordinator is a party unless there is clear personal failure.

13.6 All cases not involving complicated questions of fact or law shall be disposed of by Ombudsman within 15 (fifteen) days from the date of receipt of complaint. Other cases may be disposed of within 60 (sixty) days.

13.7 In any proceeding before the Ombudsman, if the facts reveal a case of illegal gratification, bribery or misappropriation and the Ombudsman is satisfied that the case is fit for further investigation by an appropriate court of law, the same shall be referred by the Ombudsman to the authority competent to sanction criminal prosecution of the persons involved in the case who shall take action in accordance with prescribed procedures.

13.8 Representation of parties by Advocates is not permissible.

13.9 The awards of Ombudsman would be strictly within the purview and confines of the MGNREG Act, the rules and the Schemes formulated there under and the operational guidelines issued by the Government of India from time to time.

14. Action on Reports of Ombudsman

14.1 State Government shall set up a system within the nodal department to monitor the action taken on the awards of Ombudsman. **Wherever action is not taken on the Award, which has become final, disciplinary action shall be taken against the officers concerned.**

14.2 Copy of the action taken report (ATR) shall be sent to the Ombudsman concerned immediately after action is taken and in no case more than 2 (two) months from the date of awards reported by the Ombudsman.

14.3 The summary report of cases disposed by Ombudsman and action taken on the awards shall be reported to the State Employment Guarantee Council by the Secretary, State Nodal Development in its meetings and will also form part of the Annual Report of the nodal department.

14.4 The summary report of cases disposed by Ombudsman and action taken on the awards shall also be reported to the Ministry of Rural Development, Govt. of India for placing before the Central Employment Guarantee Council, by the Secretary, State Nodal Department.

—x—x—